मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा में टिकटों के लिए संभागवार बैठकें शुरु

गुरुवार को अजमेर, उदयपुर व बीकानेर संभाग की बैठक हुई, शुक्रवार को पहली सूची की संभावना

जयपुर, 27 अगस्त। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने प्रदेश के नगर निकायों के लिए टिकटों पर अंतिम मंथन शुरू कर दिया है और अगले तीन दिनों में सात संभागों की महत्वपूर्ण बैठकों के माध्यम से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। संभागवार बैठकों में दावेदारों के नामों पर चर्चा के साथ पैनल तैयार किए जा रहे हैं, वहीं जिन सीटों पर किसी प्रकार का विवाद या मतभेद नहीं है, वहां प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, संगठन की इस कवायद के बाद शुक्रवार को पार्टी की पहली सूची जारी होने की प्रबल संभावना है।

- शुक्रवार की भरतपुर व कोटा संभाग की बैठकें आयोजित की गई हैं। बाकी संभागों की बैठक इसके बाद होगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरूवार को निकाय चुनाव की रणनीति और प्रत्याशी चयन पर विचार-विमर्श के लिए अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग की बैठक ली।

निकाय चुनाव की रणनीति और प्रत्याशी चयन पर विचार-विमर्श के लिए गुरुवार को अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग की बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में संबंधित संभाग के नगर निकायों की चुनावी स्थिति, स्थानीय समीकरणों और संभावित प्रत्याशियों के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठकों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी सहित, संबंधित संभागों के प्रभारी, वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष रूप से अजमेर संभाग की बैठक में शामिल हुए। वहीं, शुक्रवार को भरतपुर और कोटा संभाग की बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

इन बैठकों में भी नगर निकायवार दावेदारों के नामों पर विचार कर टिकटों के पैनल तैयार किए जाएंगे। शेष संभागों की बैठकों में भी इसी तरह प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। संगठन का प्रयास है कि निकाय चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, जो पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के साथ चुनावी मैदान में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बैठकों में यह भी तय किया जा रहा है कि जहां एक से अधिक मजबूत दावेदार हैं, वहां स्थानीय नेताओं और संगठन पदाधिकारियों की राय के आधार पर अंतिम फैसला किया जाए।

जे.ई.टी.-2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाला ईनामी आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 27 अगस्त। कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी)-2021 में फर्जीवाड़े के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने लंबे समय से फरार चल रहे इनामी आरोपी विशाल सैनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा दिलाने वाले गिरोह में शामिल था। आरोपी विशाल सैनी (24) श्रीमाधोपुर (सीकर) का रहने वाला है।

- पुलिस जाँच में सामने आया था कि एक संगठित गिरोह ने अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उनके स्थान पर डमी कैन्डीडेटों को परीक्षा में बैठाया था।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से प्रदेश के पांच कृषि विश्वविद्यालयों सहित, अन्य निजी विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सौंपी गई थी।

8 अगस्त 2021 को जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर में कुल 96 परीक्षा केन्द्रों पर चार वर्षीय बीएससी (कृषि, उद्यान विज्ञान, वानिकी, गृह विज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान), प्री-पीजी और प्री-पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी। जांच के दौरान सामने आया कि एक संगठित गिरोह ने अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उनके स्थान पर डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाया था।

एसओजी की जांच में सामने आया कि विशाल सैनी ने भी अपनी जगह डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाकर परीक्षा दिलाई थी। जांच में नाम आने के बाद से लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था। एसओजी ने गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

एसओजी ने फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र बेचने वाले दलाल को गिरफ्तार किया

मुख्य दलाल ओमप्रकाश कस्वां ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 में फर्जी खेल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 27 अगस्त। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 लेवल-1 में फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण-पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने मुख्य दलाल ओमप्रकाश कस्वां (35) को गिरफ्तार किया है। आरोपी चूरू जिले के सांडवा थाना क्षेत्र के जोगलसर गांव का निवासी है। आरोप है कि उसने 7 लाख रुपए लेकर फर्जी खेल प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया था। फिलहाल एसओजी की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल के अनुसार, मामले में पूर्व में गिरफ्तार बबिता जाखड़ निवासी सुजानगढ़ से पूछताछ में ओमप्रकाश की भूमिका सामने आई। बबिता ने शिक्षक भर्ती में दो प्रतिशत खेल कोटे का लाभ लेने के लिए ओमप्रकाश से 7 लाख रुपए में फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण-पत्र खरीदा था।

- आरोपी ओम प्रकाश ने 7 लाख रूपए में विशाखापट्टनम में 2017 में हुए राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैम्पियनशिप का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करा कर दिया।

जांच में सामने आया कि ओमप्रकाश ने 7 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अपने जीजा रामचन्द्र निवासी डेह, नागौर को दिए। आरोप है कि रामचन्द्र के माध्यम से विशाखापट्टनम में वर्ष 2017 में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का फर्जी प्रमाण-पत्र तैयार कराया गया। इसकी फोटो प्रति कर्मचारी चयन बोर्ड और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में जमा कराई गई थी।

शिक्षक भर्ती-2022 में खेल कोटे से कुल 38 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। जांच में सामने आया कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद की ओर से बीकानेर शिक्षा निदेशालय को भेजी गई सत्यापन रिपोर्ट फर्जी और कूटचरित ई-मेल आईडी के जरिए भेजी गई थी। इस मामले में एसओजी ने प्रकरण संख्या 98/2024 दर्ज किया था।

फर्जी ई-मेल से रिपोर्ट भेजने वाले बिमलेन्दु कुमार झा और उसके साथी कमल सिंह को एसओजी ने 7 मई 2025 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मार्च 2026 में अभियान चलाकर 21 अभ्यर्थियों, तीन सहयोगियों और तीन दलालों समेत 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओमप्रकाश की गिरफ्तारी के बाद एसओजी अब उससे नेटवर्क में शामिल अन्य दलालों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के बारे में पूछताछ कर रही है।

पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध नहीं मानेगा

इस्लामाबाद, 27 अगस्त। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंधों को मानने से इनकार करते हुए तेहरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पाकिस्तान का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वह ईरान के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखेगा।

ईरान सरकार के अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी के मुताबिक,

- पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के साथ उसके व्यापारिक संबंध बने रहेंगे।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने गुरुवार को इस्लामाबाद में साप्ताहिक प्रेसवार्ता के दौरान यह बयान दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से एकतरफा कदमों और प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है।

अंद्राबी ने कहा कि एकतरफा प्रतिबंधों के नकारात्मक प्रभाव होते हैं और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ऐसे प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक दबाव को तेहरान और वाशिंगटन के बीच व्यापक तनाव का हिस्सा बताया और विवादों के समाधान के लिए बातचीत तथा कूटनीति को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

यूपी के 62000 शिक्षक पात्रता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। तथापि, सरकारी स्कूलों में पहले से कार्यरत शिक्षकों में करीब 62,000 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं कर सके। नतीजों के आंकडों के अनुसार, 2,68,799 कार्यरत शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,06,771 शिक्षक पास हुए। यह आंकडा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीचर एलिजबिलिटी (टी.ई.टी.) पास करना अनिवार्य कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) कानून के तहत नियुक्त शिक्षकों और पदोन्नति पाने के इच्छुक कार्यरत शिक्षकों के लिए टी.ई.टी. पास करना अनिवार्य है। हालांकि, अदालत ने शिक्षक की बची हुई सेवा अवधि के आधार पर अलग-अलग समय-सीमा तय की थी। जिन शिक्षकों की पांच साल से अधिक सेवा बाकी थी, उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए दो साल के भीतर टी.ई.टी. पास करना जरूरी था। जिन शिक्षकों की पांच साल से कम सेवा बाकी थी, वे टी.ई.टी. पास किए बिना सेवानिवृत्ति तक नौकरी जारी रख सकते थे, लेकिन परीक्षा पास किए बिना पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब है कि यू.पी.टी.ई.टी 2026 में फेल होने का यह अर्थ नहीं है कि कार्यरत शिक्षक की नौकरी तुरंत चली जाएगी। इसका असर शिक्षक की नियुक्ति की स्थिति, बची हुई सेवा अवधि और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उसकी पात्रता पर निर्भर करेगा।

मुख्यमंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाषा होने के साथ ही अनेक भाषाओं की जननी भी है। इस भाषा ने धर्म और दर्शन के साथ ही चिकित्सा, योग, संगीत और साहित्य से जुड़ा ज्ञान सहेजा है।

नेपाल में तीन दिन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने बताया कि वहाँ कुछ जगहों पर पांच फीट से अधिक कीचड़ जमा हो गया, जिससे सड़क और संचार व्यवस्था बाधित हो गई। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, छोछेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम के पास एक झील बन गई है। गुरुवार सुबह तक इसमें करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और पानी पहले ही बाहर निकलने लगा था। अगले तीन दिनों में इसमें 30 लाख घन मीटर और पानी आने की संभावना है, जिससे झील के टूटने का खतरा काफी बढ़ गया है।

चीनी इंजीनियर इस संभावना से निपटने की तैयारी के लिए बाढ़ के संभावित बहाव का कंप्यूटर मॉडल के जरिए अनुमान लगा रहे हैं। वहीं, नेपाल ने भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से अगली सूचना तक नदी के किनारे से दूर रहने को कहा है।

5 स्टार में 10 दिन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सब-इंस्पेक्टर अजय राज सिंह ने बताया कि पहली नजर में यह मामला ट्रैवल एजेंसी की मिलीभगत से पर्यटक द्वारा कथित तौर पर की गई धोखाधड़ी का लगता है। मामले की जांच की जा रही है।

इससे पहले जुलाई में, तमिलनाडु के 69 वर्षीय एक व्यक्ति को पिछले तीन दशकों के दौरान पूरे भारत में 300 से अधिक आलीशान होटलों को कथित तौर पर ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, वह फर्जी पहचान का इस्तेमाल करता था और होटल के बिल का भुगतान किए बिना वहां से चला जाता था। आरोपी बिंग्सन जॉन कथित तौर पर कभी विदेशी पर्यटक गाइड, कभी अंग्रेजी शिक्षक और कभी योग प्रशिक्षक बनकर 5-स्टार होटलों में कमरा बुक करता था। पुलिस ने बताया कि वह कई दिनों तक होटल में रहता, होटल की सुविधाओं का इस्तेमाल करता और फिर बिल चुकाए बिना गायब हो जाता था। उस पर कभी-कभी होटल की कीमती चीजें अपने साथ ले जाने का भी आरोप था।

भागवत के कार्यक्रम संयोजकों का एक्स अकाउन्ट सस्पैंड हुआ

वे 29 को न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर में ''यूनिवर्सल वननैस सेलिब्रेशन'' कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हैं

न्यूयॉर्क, 27 अगस्त। अमेरिका के न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विवाद और बढ़ गया है। कार्यक्रम के आयोजक, अमेरिकन हिंदूज़ फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग का सोशल मीडिया मंच एक्स अकाउंट निलंबित कर दिया गया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी कार्यक्रम और आरएसएस के प्रति अपना विरोध जता चुके हैं। वहीं, अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भी भागवत का वीज़ा रद्द करने की मांग की है। एक्स पर आयोजकों का अकाउंट अब उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। संगठन ने कहा है कि यह निलंबन गलती से हुआ हो सकता है। संगठन के अनुसार, उसके संचार में शांति, एकता, सद्भाव और अलग-अलग धर्मों व संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया गया है और उसने एक्स की नीतियों का पालन किया है।

मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्थित इंफोसिस थिएटर में 'यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन' कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे। भागवत इस समय अमेरिका, कैनडा और ब्रिटेन की तीन देशों की यात्रा पर हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर न्यूयॉर्क में राजनीतिक विवाद भी सामने आया है।

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा है कि वे आरएसएस या प्रस्तावित कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर प्रशासन के पास है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। ममदानी ने आरएसएस की विचारधारा का भी विरोध किया और इसे देश की समावेशी सोच के लिए चिंताजनक बताया। उनके बयान पर भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी सलाहकार संस्था यूएससीआईआरएफ ने ट्रंप प्रशासन से मोहन भागवत का वीजा रद्द करने की मांग की है। संस्था ने आरएसएस से जुड़े संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक हमलों का आरोप लगाया है। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए यूएससीआईआरएफ को पक्षपाती और विश्वसनीयता से रहित संगठन बताया है।

'मूड ऑफ द नेशन सर्वे का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पक्ष में काफी बदल गया है।

सर्वे भाजपा की केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकारों से जुड़े विवादों की संभावित राजनीतिक कीमत की ओर भी इशारा करता है। 47 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी विवाद का नरेन्द्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, दोनों सरकारों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। वहीं, 8 प्रतिशत लोगों का मानना था कि इसका असर केवल केन्द्र सरकार पर पड़ा, जबकि 7 प्रतिशत ने कहा कि इसका प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार तक सीमित रहा।

उत्तर प्रदेश के आंकड़े राष्ट्रीय तस्वीर के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हैं। हाल के युवा आंदोलनों और राजनीतिक असंतोष के बावजूद भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनी हुई है। हालांकि अगस्त के एमओटीएन सर्वे में, भाजपा को 326 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जो जनवरी के अनुमान से 26 कम है। यानी सत्तारूढ गठबंधन की कुल बढ़त मजबूत रहेगी, पर इसके बावजूद कुछ क्षरण के संकेत दिखाई दे रहे हैं।

मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे समूह द्वारा कराया जाने वाला द्विवार्षिक सर्वे है, जो करीब दो दशक से आयोजित किया जा रहा है। अगस्त 2026 का सर्वे सी-वोटर ने किया। इसमें 1 जुलाई से 25 अगस्त के बीच 25,184 लोगों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार किए गए। इसके अलावा सी-वोटर की नियमित ट्रैकिंग प्रक्रिया के तहत, पिछले छह महीनों में किए गए 91,795 साक्षात्कारों को भी इसमें शामिल किया गया।

भाजपा के लिए तत्काल चिंता आंकड़ों से कम और उत्तर प्रदेश में बदलती राजनीतिक दिशा से अधिक है। वर्ष 2024 के चुनाव में विपक्ष को स्पष्ट बढ़त देने वाला यह राज्य एक बार फिर इंडिया गठबंधन की ओर झुकने के संकेत दे रहा है।

यदि यह रुझान जारी रहता है, तो अगला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को कहीं अधिक कड़े मुकाबले का मैदान बना सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बनाए रखने की भाजपा की रणनीति को भी जटिल कर सकता है।

लॉ स्टूडेंट्स ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनकी डिग्रियां ''अनुपस्थिति'' में प्रदान की जाएंगी।

सूचना में कहा गया, 23 अगस्त, 2026 को अकादमिक प्रशासन टीम ने स्नातक छात्रों को ईमेल भेजकर 12 सितंबर, 2026 को वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित करने की प्रस्तावित तारीख की जानकारी दी थी। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हम 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं कर सके।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कहा कि स्नातक छात्रों को उनकी डिग्रियां कूरियर से भेजी जाएंगी। इन्हें कैंपस से भी लिया जा सकता है।

सूचना में आगे कहा गया, विश्वविद्यालय आज कुछ समय बाद सभी स्नातक छात्रों के साथ नया फॉर्म और प्रक्रिया साझा करेगा, ताकि वे अपनी पसंद का विकल्प चुन सकें।

यह घटनाक्रम नलसार विवाद की पृष्ठभूमि में सामने आया है। ज्ञातव्य है कि हैदराबाद स्थित इस लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश की प्रस्तावित मौजूदगी का विरोध किया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की उस मामले में दखल देने के लिए आलोचना भी की थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह उनके और छात्रों के बीच का मामला है।

ट्रंप की ''कभी न हारने वाले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए उनके अपने हित भी हैं। राइश के मुताबिक, यह स्थिति अमेरिकी शक्ति के प्रदर्शन के बजाय उसकी सीमाओं को दिखाने का जरिया और बन गई है।

उनका तर्क है कि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि ट्रंप का बाकी जगहों पर भी रवैया ज्यादा आक्रामक क्यों होता जा रहा है।

जब ट्रंप को विरोध का सामना करना पड़ता है, तो वो पीछे नहीं हटते, बल्कि टकराव को और बढ़ाते हैं। कोई संस्था उन्हें चुनौती देती है तो वे उस संस्था पर हमला करते हैं। अदालतें उन्हें रोकती हैं तो वे दूसरा रास्ता तलाशते हैं। सहयोगी देश विरोध करते हैं तो उन्हें धमकाते हैं। राइश की व्याख्या में उद्देश्य अब किसी सुसंगत नीतिगत परिणाम को हासिल करने से अधिक यह साबित करना होता जा रहा है कि कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता।

कैनडा इसका शायद सबसे स्पष्ट उदाहरण है। राइश के अनुसार, कैनडा से होने वाले आयात पर भारी शुल्क लगाने का ट्रंप का फैसला एक तरह की राजनीतिक भरपाई की कोशिश थी, एक ऐसी लड़ाई जिसे जीत के रूप में पेश किया जा सके, ऐसे समय में, जब दूसरे मोर्चों पर जीत हासिल करना कठिन होता जा रहा हो। लेकिन कैनडा ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे ट्रंप की जबरदस्ती करने की कोशिश अमेरिकी वर्चस्व के त्वरित प्रदर्शन के बजाय एक और टकराव में बदल गई, जबकि वे शायद कुछ और ही चाहते थे।

यह प्रतिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ट्रंप की, सावधानी से बनाई गई ''बेहतरीन ड्रीममेकर'' छवि को चुनौती देती है, जिसमें वे खुद को सर्वोच्च सौदेबाज के रूप में पेश करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता है, सामने वाला झुक जाता है और ट्रंप जीत की घोषणा कर देते हैं।

राइश का कहना है कि अब इसका उलटा हो रहा है। सहयोगी देश विरोध कर रहे हैं। विदेशी सरकारें वॉशिंगटन की इच्छाओं के आगे झुकने से इनकार कर रही हैं। विश्वविद्यालय उनके निर्देशों का विरोध कर रहे हैं। मीडिया संस्थाएं उन्हें अदालत में चुनौती दे रही हैं। उनकी अपनी पार्टी के सदस्य उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। और बाजार, जिन्हें राष्ट्रपति की बयानबाजी से डराया नहीं जा सकता, उनकी आर्थिक और राजकोषीय नीतियों को लेकर अपनी चिंताओं के संकेत दे रहे हैं।

इन सभी घटनाओं का सामूहिक प्रभाव किसी एक घटना या झटके से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

ट्रंप की राजनीतिक शक्ति काफी हद तक इस धारणा पर टिकी रही है कि वे अजेय हैं। समर्थक ऐसे नेता के पीछे लामबंद होते हैं, जिसके बारे में उनका विश्वास है कि वह हमेशा जीतता है। वहीं विरोधी इस बात से डर जाते हैं कि ट्रंप को चुनौती देने की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन एक बार जब यह धारणा खत्म हो जाती है तो पूरा समीकरण बदल जाता है।

यही वजह है कि राइश ट्रंप के लगातार टकरावों को उनके लिए आत्मघाती मानते हैं। हर वह धमकी जो सामने वाले को झुकाने में विफल रहती है, हर वह नीति जो जवाबी कार्रवाई को जन्म देती है और हर वह संस्थागत चुनौती जो उनके दबाव के बावजूद कायम रहती है, उनकी ताकत की छवि को और कमज़ोर करती है।

विडंबना यह है कि ट्रंप शायद इस गिरती स्थिति का जवाब और अधिक आक्रामक होकर दे रहे हैं और यही व्यवहार उनकी कमज़ोर होती स्थिति को और अधिक साफ तौर पर सामने ला रहा है।

राइश का निष्कर्ष यह है कि ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या शायद यह नहीं है कि वे अलग-अलग लड़ाइयां हार रहे हैं, बल्कि यह है कि दुनिया अब उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर रही है, जो हार भी सकता है।

जिस राष्ट्रपति की पूरी राजनीतिक छवि खुद को अंतिम विजेता साबित करने पर टिकी हो, उसके लिए यही शायद सबसे निर्णायक हार हो सकती है।

दिल्ली एनसीआर में प्याज़ 35 रूपए किलो के भाव बिका

केन्द्र सरकार ने बफर स्टॉक से 1.21 लाख टन प्याज़ बाज़ार में उतारा, ताकि दामों में कटौती की जा सके

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 27 अगस्त। केन्द्र सरकार गुरुवार से राष्ट्रीय राजधानी में उपभोक्ताओं को 35 रुपये प्रति किलो की रियायती कीमत पर सीधे प्याज बेचना शुरू करेगी। इसका उद्देश्य प्याज की बढ़ती कीमतों को कम करना है, जो इस समय 55-60 रुपये प्रति किलो के आसपास हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाजार में उतारा जा रहा प्याज, 2026 के लिए प्याज उत्पादक राज्यों में रखे गए 1.21 लाख टन के बफर स्टॉक से लिया जा रहा है। केन्द्र सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का इस्तेमाल कर रही है। खुदरा बिक्री नाफेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) और केन्द्रीय भंडार के आउटलेट्स के जरिए की जाएगी।

एनसीसीएफ 100 केन्द्रीय भंडार स्टोरों के जरिए उपभोक्ताओं को सीधे प्याज बेचेगा। वह दिल्ली-एनसीआर में

- बुधवार तक 55 से 60 रूपए किलो के भाव तक प्याज़ की बिक्री हुई थी।

मदर डेयरी के आउटलेट्स के जरिए भी बिक्री बढ़ाने की योजना बना रहा है।

एनसीसीएफ के पास प्याज का 62,000 टन का बफर स्टॉक है और वह महाराष्ट्र के नासिक से 400 टन प्याज दिल्ली ला रहा है। कांदा एक्सप्रेस के गुरुवार को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।

नाफेड के पास 55,000 टन से कम प्याज का बफर स्टॉक है। वह भी दिल्ली और कोच्चि तथा गुवाहाटी समेत, अन्य केन्द्रों पर प्याज बेचेगा। प्याज से लदी पहली ऐसी मालगाड़ी, जिसमें 800 टन प्याज है, नासिक से रवाना हो चुकी है और दिल्ली पहुंच रही है।

दिल्ली के अलावा चार अन्य केन्द्रों -चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै और गुवाहाटी-में भी इस उद्देश्य के लिए चलाई जा रही विशेष मालगाड़ियों के जरिए प्याज की आपूर्ति की जाएगी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी और रायपुर में भी यह योजना शुरू करने का इरादा रखती है।

इस बीच, महाराष्ट्र के नासिक और लासलगांव के थोक बाजारों में प्याज की कीमतें गिरने लगी हैं। यह गिरावट सरकार की बाजार में हस्तक्षेप करने की घोषणा के बाद आई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे महंगाई बढ़ने की आशंका कम हुई है, जो कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह बन रही थी।

यह कदम पिछले एक महीने में प्याज की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी के बीच उठाया गया है। देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 25 अगस्त को 28 प्रतिशत से अधिक बढ़कर, 44.72 रुपये प्रति किलो हो गई, जबकि एक महीने पहले 25 जुलाई को यह 34.80 रुपये प्रति किलो थी। एक साल पहले प्याज 28.67 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। इसकी तुलना में अब कीमत 56 प्रतिशत बढ़ चुकी है।

पंजाब की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व्यवहार को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। फरलो जेल से मिलने वाली ऐसी छुट्टी है, जिसके लिए किसी विशेष या आकस्मिक कारण की आवश्यकता नहीं होती। यह पात्र कैदियों को नियमों और निर्धारित शर्तों के अधीन मिलने वाला वैधानिक लाभ है। प्रत्येक राज्य में कैदियों को फरलो देने के लिए अपने अलग नियम और दिशानिर्देश होते हैं। राम रहीम को मिली ताजा फरलो 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि फरलो चुनावी लाभ के लिए दी गई है, लेकिन इसका समय संदेह पैदा करने वाला है और इसको लेकर राजनीतिक सवाल उठना सम्भावित है।

मराठी सीखने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अगस्त को मुंबई में ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा तीन दिन की हड़ताल शुरू किए जाने के दो दिन बाद लिया। चालक मराठी भाषा संबंधी निर्देश के विरोध में हड़ताल पर गए थे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908